

विमुद्रीकरण



सरोज बाला मोनू

रिसर्च स्कोलर

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर राजस्थान। भारत।

विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान में प्रचलित मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई मुद्रा को लाया जाता है। ऐसा ही कुछ दिन पूर्व भारत में देखने को आया है। 8 नवम्बर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 500 व 1000 के नोटों को पूर्णतया बंद कर उनके स्थान पर नई मुद्रा को चालू किया हैं। देखने पर उनका ये कदम सबको बहुत अच्छा लगा है किन्तु हर एक सिक्के के दो पहलु होते हैं। जहां भी कोई नया काम होता है वहां सबको कुछ आलोचनाएं तो कुछ परेशानी अवश्य उठानी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे यहां देखने को मिला हैं। कुछ लोग पक्ष तो कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं। परन्तु जो भी हुआ सो हुआ अब देखना ये है कि ये हमारे लिए कितनी मूल्यवान और कितनी नुकसानदायक हो सकती है। अरस्तु ने कहा भी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यहां वो ही जिन्दा रह पायेगा जिसने अपने को उस परिवर्तन के अनुसार ढाल लिया हैं।

विमुद्रीकरण का इतिहास

विमुद्रीकरण इसका इतिहास काफी पुराना है। अनेकों विकसित देशों जैसे ब्रिटेन व कनाडा और चीन आदि ने बहुत पहले ही अपनी मुद्राओं को नया रूप दे दिया था जबकि भारत में विमुद्रीकरण की प्रक्रिया काफी देरी से शुरू हुई। हमारे भी यहां इसका इतिहास काफी पुराना है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1938 व 1954 में 10000 रुपये का नोट छपा गया था किन्तु इन्हें 1946 में पहली बार व 1978 में दूसरी बार बंद किया गया। विमुद्रीकरण के द्वारा इनके स्थान पर 500 व 1000 के नोट जारी किये गये।

सरोज बाला मोनू

1Page

हालांकि प्रचलित नोटों को भी प्रधानमंत्री इन्द्रा गांधी ने विमुद्रीकरण के द्वारा बंद करने का प्रयास किया किन्तु उस समय ये नहीं हो पाया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आई जिसके लिए मुद्रा को नये सिरे से लाना पड़ा ? कौन लोग हैं जो देश में काला धन छुपाये बेटें हैं ? क्या विमुद्रीकरण से काले धन को समाप्त करने में कुछ मदद मिली ? या अब भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया ? या आम आदमी को इससे कुछ भायदा मिला ? या विदेशों में जमा काला धन वापिस आया? अनेकों ऐसे सवाल हैं जो आज भी विमुद्रीकरण के बाद भी आम जन को कचोट रहे हैं। विमुद्रीकरण के कुछ लाभ व कुछ हानियां भी हुई व भी होंगे जो इस प्रकार हैं।—

विमुद्रीकरण के लाभ:—

आयकर में फायदेमंद:—

जो भी हो पर 125 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 ही आयकर भरते हैं और बाकि एक करोड़ इसे काले धन के रूप में छुपाते रहते हैं। अब जो कैशलैश इकोनोमी की बात हो रही है तो इससे देश की एक बड़ी आबादी का पैसा कर के रूप में सरकार को मिल पायेगा।

कालेधन को कम करने में सहायक:—

विमुद्रीकरण से हमें पूर्ण रूप से तो नहीं किन्तु कुछ हद तक काले धन को समाप्त करने में सहायता अवश्य मिलेगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने धन को विदेशों में छुपा रहा है। इससे वह लाखों का मालिक बन बैठा है किन्तु अब वह ऐसा नहीं कर पायेगा क्योंकि पहला कारण तो मुद्रा का विमुद्रीकरण हो चुका है दूसरा अन्य देश भी सन्देह में रहेंगे। अतः कुछ हद तक काले धन पर रोक अवश्य लगेगी।

रियल इस्टेट में सहायता:—

अभी जो भी हालात हो किन्तु आगामी वर्षों में रियल सेक्टर में काफी उम्मीद नजर आ रही है। अभी जो मुद्रा की कमी चल रही है वो आने वाले दिनों में कुछ सुधरेगी व रियल सेक्टर में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है।

चुनावों में खर्चों में कमी:—

वर्तमान दौर जहां एक और विमुद्रीकरण का वहीं दूसरी और चुनावों का भी है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में व उत्तराखंड और पंजाब सहित कुल पांच राज्यों में चनाव हो रहे हैं व इस समय देश में विमुद्रीकरण का आना काफी धन बरबाती को रोकेगा।

डिजिटल इकोनोमी को बढ़ावा:-

विमुद्रीकरण के साथ ही एक नई प्रक्रिया भी आ गई है जो देश के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आज जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं वह आने वाले दिनों में हमें विकाससिल से विकसित भी बना सकती है क्योंकि इससे देश में भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिलगी।

विमुद्रीकरण के नुकसान:-

जहां हमें विमुद्रीकरण के अनेकों फायदें नजर आ रहे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।

चार्लस डार्विन ने एक बार कहा था कि मेरे जन्म के साथ ही सुख दुख का जन्म हुआ है पर ये मुझ पर है कि मैं कैसे जीवन को जीता हूं। इसी प्रकार वि के जन्म के साथ ही कुछ लाभ तो कुछ हानियां जन्मी है और यह हम पर है कि हम इसको कैसे लेते हैं।

आम जनता को परेशानी :-

जब से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया की घोषणा हुई उस दिन से ही सबसे ज्यादा परेशानी तो आम आदमी को उठानी पड़ी है। उदाहरण के लिए मैं खुद छात्रा होकर भी कुछ दिन अपनी आवश्यक चीजें नहीं ला पायी और हर रोज पता नहीं कितना समय एटीएम की लाईनों में बरबाद किया। इसी तरह पूरे देश में लाखों लोगों को परेशान होते भी देखा है। कितने लोग अपनी जाने भी गंवा चुके हैं—परन्तु सरकार के पास अभी भी पूर्णतः समाधान नहीं है। क्यों ?

कैशलेस अर्थव्यवस्था पूर्णतः असम्भव:-

जहां एक ओर सरकार नकदी रहित इकोनोमी की बात कह रही है तो ऐसी करना महज एक सपना हो सकता है क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और एक करोड़ में से 40 प्रतिशत के पास आज भी बैंक खाता नहीं है। ऐसे में हम कैसे नकदी रहित अर्थव्यवस्था की बात समभव कर सकते हैं। अगर देश को वास्तव में ही ऐसा बनाना है तो सबसे पहले गांवों को कैशलेस बनाना होगा और सबका बैंक खाता भी खुलावाना होगा। वरना ये सबकुछ असम्भव है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा:-

एक ओर देश के विकास की बात करते हुये विमुद्रीकरण किया है किन्तु इससे तो भ्रष्टाचार में कोई सुधार नजर नहीं आया क्योंकि हमने देखा कि बैंकों की लाईनों में भी वो आम

आदमी लगा जबकि काले धन वाले तो सीधे बैंक अफसरों से मिलकर काला धन रातो रात ही सफेद कर लिया। इसी का परिणाम है कि देश के टोप बैंकों के कर्मचारी हिरासत में आये।

साईबर कार्डिन में वृद्धि:-

दूसरी और डिजिटल इकोनोमी से भी हैकर बैंक खातों के पासवर्ड हैककर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी और हमारे देश में आज भी साईबर कार्डिन के लिए इतने सख्त कानून नहीं जितने की विदेशों में। इसी कारण आज भी हमें साईबर सुरक्षा के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि सबसे पहले देश में साईबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाये।

छोटे उधमियों को नुकसान:-

जबसे देश में नोटबंदी को लागू किया गया है तब से छोटे उधमियों को काफी परेशानी हुई है। एक और जहां उनके रोटी रोजी के कमाने का साधन था वह भी बंद सा हो गया तो दूसरी और उनके काम काज में कमी आई है। जहां बड़े उधमियों के पास अनेकों साधन होते हैं वन्ही छोटे उधमियों के पास इतना कुछ भी नहीं होता कि वो बिना कुछ किये जीवन यापन कर सकें।

नोटबंदी से कई बड़े घोटाले:-

देश के सबसे शीर्ष बैंक एक्सिस के कई कर्मचारियों को पकड़ा जाना बड़ी शर्म की बात है। दर्जनों मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां कोटिल्य का कहना भी ठीक है कि राजा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए और वो सब भी यहा देखा गया। काले धन से जो कर पहले मिल रहा था वो भी शायद अब मिल पायेगा क्योंकि अब वह 40 करोड़ बैंक खातों में बंट बंटकर गोरा हो गया है। ये सब देखकर सर्वोच्च न्यायालय तक को दखल देना पड़ा है क्योंकि आम लोग लाईनों में मर रहे हैं जबकि अमीर लोग घरों में मजे से काला धन सफेद कर रहे हैं।

आटोमोबाइल्स बिक्री में गिरावट:-

नोटबंदी से दिसम्बर में वाहनों की बिक्री 18.66 प्रतिशत गिर गई। यह 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दिसम्बर 2000 में बिक्री 21.181 प्रतिशत घटी थी। सियाम के अनुसार पिछले महीने 12.21929 वाहन बिके जबकि पिछले साल दिसम्बर में 15.02314 वाहनों की बिक्री हुई थी। दूसरी और दोपहिया में गिरावट सियाम के 19 साल में सबसे ज्यादा है।

घरों की बिक्री में कमी:—

प्रोपर्टी कंसल्टेंट नाइट के अनुसार नोटबंदी से बड़े शहरों में घरों की बिक्री 44 प्रतिशत तक गिरी है। यह 6 सालों में सबसे कम है। एक साल पहले इस तिमाही में 73000 घर बिकें वहीं इस साल यह 53000 के लगभग हुई है। 2015 की तुलना में इस साल 9 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इस तरह से कुल मिलाकर नोटबंदी से प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट हुई है।

देश की जीडीपी में कमी:—

नोटबंदी से देश की जीडीपी में कमी का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार देश की जीडीपी 6% प्रतिशत व रिजर्व बैंक के अनुसार देश की विकास दर 7 रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर देश की अनुमानित विकास दर लगभग 6 व 7 के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर देश की विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कम ही रहेगी।

उपसंहार:—

विमुद्रीकरण की प्रक्रिया से देश को जहां एक ओर मंदी की स्थिति का सामना करना पड़ा है वहीं दूसरी ओर आगामी वर्षों में इसके कुछ फायदें भी दृष्टिगोचर होंगे। उदाहरण के लिए किसी भी चीज का अपना एक समय होता है उसके बाद वह वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है। इसी प्रकार मुद्रा को भी समय के अनुसार बदलना जरूरी होता है। किन्तु भारत में मुद्रा के विमुद्रीकरण को लागू करने में जो परिस्थितियां पैदा हुईं वो काफी विचारनीय है मुदा है क्योंकि एक ओर जहां देश की सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक के बार बार नियमों की तबदीली से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहां पर हमें स्वामी विवेकानन्द जी की एक बात याद रखनी चाहिए:—किसी भी नाविक नाव को चलाने से पहले भलि भांति चेक कर लेना चाहिए कि नाव गंतव्य तक आराम से पहुंच पायेगी की नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नाव रास्ते से भटक जाये और उसमें बैठे यात्रियों को परेशान होना पड़े। इसी प्रकार कोई भी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि काम शुरू होने से पहले ही आलोचनाओं का सामना करना पड़े जैसा कि मोदी जी का विमुद्रीकरण का सवाल हो या रिजर्व बैंक की नितियों को क्रियान्वयन का कार्य। दोनों ही सरकारी संस्थाएं अपने पहलुओं को सही रूप से करने में उतना सफल नहीं हो पायी जितना इन्हें होना चाहिए था।

जो भी अच्छा या बुरा हुआ हो पर मेरे विचार से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक अच्छी सिद्ध होगी। लोकतंत्र का कार्य लोगों की भलाई करना है व इसमें जो भी निर्णय



हमारी सरकार लेती है वो काफी सोच विचार कर लिए जाते हैं। अतः आवश्यकता है विमुद्रीकरण को सफल बनाने की व आम जन को आने वाली परेशानी को कम करने की क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और कोई भी नीति तभी सफल मानी जाएगी जब वो इन 70 प्रतिशत लोगों के पक्ष में हो। अतः सरकार को जनता की परेशानियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए तभी वि सफल सिद्ध होगी व भारत की पहचान विदेशों में भी और ज्यादा बढ़ेगी। वरना जो कैशलेस व डिजिटल अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त की जो बात कहीं जा रही है वो सब एक कागजों में बंद फाईलें बन कर रह जाएगी।

संदर्भसूची

विमुद्रीकरण और काला धन (सी राजचद्रा रैडी)

विमुद्रीकरण डीकोडीड (ज्योति राव)

विमुद्रीकरण और अर्थव्यवस्था (किरण प्रभा)

विमुद्रीकरण एक विकास का आधार (अरुण कुमार)

विमुद्रीकरण और विकास (सीमा शर्मा)

www.hindustantimes.com

www.indianexpress.com